खबर संक्षेप

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न, आवश्यक निर्णय लिए गए

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपत्तियों के पंजीयन हेतु निर्धारित की जाने वाली गाइडलाइन दरें तर्कसंगत, व्यावहारिक तथा वास्तविक बाजार मूल्यों के अनुरूप तय की जाएं, ताकि आम नागरिकों को पंजीयन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि नागरिक कलेक्टर गाइडलाइन से संबंधित अपने सुझाव एवं प्रस्ताव 16 मार्च तक जिला पंजीयक कार्यालय तथा संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि मार्च माह में आने वाले सभी सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी जिले के पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे संपत्ति पंजीयन संबंधी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। बैठक में जिले में संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन पर विस्तृत चर्चा की गई।

जल संरक्षण में आमजन निभाएं अपनी सहभागिताः सीईओ

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह ने 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जिला पंचायत सभागार में जनपद पंचायत सोहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में जिले में 19 मार्च से 30 जून 2026 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें। बैठक में पुराने तालाबों, कुओं, बावड़ियों एवं अन्य जल स्रोतों की साफ-सफाई तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विधायक ने धनपुरी में वृहद स्टेडियम निर्माण हेतु किया भूमि पूजन

शहडोल। विधायक जैतपुर जय सिंह मरावी ने नगर पालिका धनपुरी के वार्ड क्रमांक 6 में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वृहद स्टेडियम का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होनें कहा कि स्टेडियम के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों को खेलने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। नगरपालिका धनपुरी में आमजन की सुविधाओं के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला योजना समिति की सदस्य श्रीमती अमिता चपरा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रविंद्र कौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री पूजा बुनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे।

बुढ़ार थाना वसूली कांड में नया मोड़

पीड़ितों ने शपथपत्र देकर एसपी से मांगी एफआईआर

शहडोल। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में कथित अवैध वसूली और मारपीट के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पहले सामने आए आरोपों के बाद अब पीड़ित दुर्गेश प्रजापति और रवि प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक शहडोल को शपथपत्र के साथ लिखित शिकायत देकर बुढार थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार और प्रधान आरक्षक चेतराम कौशिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। पीड़ितों का आरोप है कि उनसे मारपीट कर धमकी देते हुए रिश्वत ली गई और विरोध करने पर झूठे मामलों में फंसाने की चेतावनी दी गई।

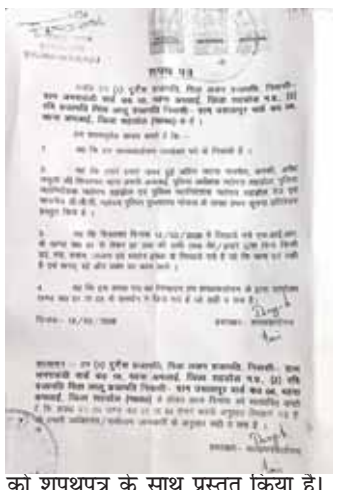

पीड़ितों ने एसपी को सौंपी लिखित शिकायत

अवैध वसूली और मारपीट के आरोपों से जुड़े इस मामले में ग्राम अमलई निवासी दुर्गेश प्रजापति और रवि प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक शहडोल को विस्तृत शिकायत सौंपी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बुढार थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक चेतराम कौशिक ने थाना प्रभारी के नाम पर उनसे पैसे की मांग की और न देने पर मारपीट व धमकी दी गई।

शपथपत्र के साथ लगाए गंभीर आरोप

पीड़ितों ने इस बार केवल शिकायत ही नहीं दी, बल्कि पूरे मामले से जुड़े आरोपों को शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिए ऑडियो, वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग सहित डिजिटल साक्ष्य भी सुरक्षित रखे हैं, जिन्हें जांच के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

झूठे केस में फंसाने की आशंका जताई

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि उन्होंने इस मामले में आवाज उठाई तो उनके खिलाफ झूठे और गंभीर प्रकरण दर्ज किए जा सकते हैं। पीड़ितों ने आशंका जताई है कि बदले की भावना से उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकती है।

हरिभूमि
विराट भूमि
कैमरे में कैद राम राज के रिश्वतखोर वर्दीधारी
(स्टिंग ऑपरेशन)

पहले भी सामने आए थे वसूली के आरोप

इस मामले में पहले सामने आई जानकारी के अनुसार ईंट भट्टा संचालकों से कथित रूप से अवैध वसूली किए जाने की बात सामने आई थी। आरोप था कि प्रधान आरक्षक द्वारा थाना प्रभारी के नाम पर 30 हजार रुपये की मांग की गई, जिसे बाद में 17 हजार रुपये में तय कर लिया गया।

नकद और डिजिटल माध्यम से पैसे लेने का आरोप

शिकायत में बताया गया है कि 26 फरवरी को अमलाई थाना क्षेत्र स्थित एक घर में बुलाकर लगभग 6,900 रुपये नकद और 5,000 रुपये मोबाइल ट्रांसफर के माध्यम से लिए गए। इसके बाद 2 मार्च को फिर फोन कर बुलाया गया और 3,000 रुपये नकद तथा 2,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए जाने का आरोप लगाया गया है।

डिजिटल साक्ष्य होने का दावा

पीड़ितों का दावा है कि पूरी घटना से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के प्रमाण उनके पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच की जाए तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई शिकायत

इस मामले की शिकायत केवल पुलिस अधीक्षक शहडोल को ही नहीं, बल्कि पुलिस महानिरीक्षक शहडोल रेंज, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश और पुलिस मुख्यालय भोपाल को भी भेजी गई है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।

एसपी की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

जब यह मामला पहली बार सामने आया था तब पुलिस अधीक्षक शहडोल रामजी श्रीवास्तव ने कहा था कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब शिकायत दिए जाने के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी जांच या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाला पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। वही इस मामले में पीड़ितों का कहना है कि यदि पुलिस न्याय नहीं मिलती है तो वह खुद तथा परिवार की जान माल की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, इसके लिए परिवाद लगाने की तैयारी भी की जा रही है।

नपा अध्यक्ष का वन अमले से खुल्लम-खुल्ला टकराव

वर्दी को दिखाई धौंस, रुकवाया सरकारी काम

शहडोल। सत्ता का नशा जब सिर चढक़र बोलता है, तो कानून की मर्यादाएं बौनी पड़ जाती हैं। ब्यौहारी नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा नेता राजन गुप्ता ने एक बार फिर अपनी कार्यशैली से विवादों का बवंडर खड़ा कर दिया है। ताजा मामला वन विभाग की जमीन पर मुनारा निर्माण रोकने और वन कर्मियों को सरेआम फटकारने का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है।

घटना ब्यौहारी वन परिक्षेत्र के बीट बेढरा की है, जहां वन विभाग की टीम शासकीय पीसीडी कार्य के तहत मुनारा (सीमांकन) निर्माण करा रही थी। विभाग का उद्देश्य वन भूमि को सुरक्षित करना और भविष्य के अतिक्रमण को रोकना था। जैसे ही जेसीबी ने गड्ढे खोदना शुरू किया, माननीय अध्यक्ष राजन गुप्ता लाव-लश्कर के साथ मौके पर पहुँच गए और सिंघम स्टाइल में काम रुकवा दिया।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अध्यक्ष महोदय वन कर्मियों पर किस कदर आगबबूला हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उन्होंने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को यहाँ तक कह डाला कि जेसीबी को जब्त कर नगर पालिका खड़ा करवा दूंगा। जब रेंजर मौके पर पहुँचे, तो अध्यक्ष ने उनसे भी दस्तावेज दिखाने की जिद करते हुए तीखी बहस की। रसूख के आगे बेबस वन अमले को आखिरकार काम बंद कर बैरंग लौटना पड़ा।

यह पहली बार नहीं है जब राजन गुप्ता का रौब चर्चा में आया हो। इससे पहले टोल नाके पर कर्मचारियों से गाली-गलौच और सरेआम धमकी देने का उनका कारनामा पूरे जिले ने देखा था। सवाल यह उठता है कि क्या सत्ताधारी दल का बिल्ला लगा लेने से किसी नेता को सरकारी काम में बाधा डालने और लोक सेवकों को अपमानित करने का लाइसेंस मिल जाता है। एक तरफ सूबे की सरकार वनों के संरक्षण की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता वन सीमांकन के कार्य में रोड़ा अटका रहे हैं। आखिर राजन गुप्ता को मुनारा निर्माण से क्या आपत्ति है? क्या इस जमीन के पीछे कोई और खेल छुपा है? इस घटना ने प्रशासन के इकबाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

इनका कहना है...

जनप्रतिनिधि लोगो के सुख-दुख में खड़े होते है, वन विभाग द्वारा एक गरीब असहाय के चाय पान के टपरे के सामने जबरदस्ती निर्माण कार्य करा रहे थे, जबकि वह राजस्व नगरपालिका की जमीन है।

राजन गुप्ता
अध्यक्ष
नगर परिषद ब्यौहारी

53 साल की सेवा पर षड्यंत्र का ग्रहण

क्रिश्चियन हॉस्पिटल की अरबों की संपत्ति पर अपनों की नजर

शहडोल। सेवा के नाम पर चल रहे संस्थानों में जब लालच का घुन लग जाए, तो क्या हश्र होता है, इसका जीता-जागता उदाहरण क्रिश्चियन हॉस्पिटल ईएलसीइन एम पी बन गया है। अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी कर एक महिला और उसके सहयोगियों पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के ऐसे कारनामे उजागर किए हैं, जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। आरोप है कि अस्पताल की सेवा बंद कराकर उसकी संपत्तियों की बंदरबांट का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है।

विगत 53 वर्षों से निर्विघ्न रूप से चल रहे इस अस्पताल को सन 2010 में कूट रचित दस्तावेजों और षड्यंत्रकारियों के जाल में फंसाकर बंद करा दिया गया। प्रबंधन का सीधा आरोप है कि शिल्पा जॉली टांडी और उनके गुर्गों ने अस्पताल के विरुद्ध फर्जी कहानियां गढ़ीं। हैरानी की बात यह है कि जिस घर में शिल्पा टांडी रह रही हैं, वह अस्पताल द्वारा उनके पति को आवंटित किया गया था, लेकिन आज वही अस्पताल के अस्तित्व को मिटाने पर तुली हैं।

अस्पताल प्रबंधन ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एफ.सी.आर.ए. मद से प्राप्त चार गाडिय़ां बिना किसी अनुमति के सरेआम बाजार में बेच दी गईं। अस्पताल का कीमती जनरेटर और अन्य मेडिकल उपकरण भी खुर्द-बुर्द कर दिए गए। आरोपी महिला के विरुद्ध पहले ही 3 एफआईआर और 16 शिकायतें दर्ज हैं, फिर भी उनकी अवैध वसूली और हस्तक्षेप जारी है। बिशप सुरेन्द्र सुक्का और प्रधान कोषाध्यक्ष अशोक चौकसे ने कहा है कि माननीय हाई कोर्ट के 4 फैसले ईएलसीइन एमपी के पक्ष में हैं। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि प्रबंधन को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए। बावजूद इसके, माफिया तत्व अस्पताल को फिर से शुरू करने में रोड़ा अटका रहे हैं। प्रबंधन ने मांग की है कि जिस महिला पर कोर्ट की अवमानना और धोखाधड़ी के इतने केस हैं, उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अस्पताल प्रबंधन आज भी 30 बेड के साथ आई वार्ड शुरू करने को तैयार है, ताकि गरीबों का इलाज हो सके। अब गेंद प्रशासन के पाले में है।

अवैध मुरूम ढो रहे हाइवा और ट्रैक्टर जब्त

शहडोल। जिले में खनिज संपदा की लूट मचाने वाले माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने अब अपना शिकंजा और कस दिया है। कलेक्टर के सख्त तेवरों के बाद खनिज विभाग की टीम ने गुरुवार को ब्यौहारी क्षेत्र में बड़ी स्ट्राइक की है। यहां अवैध रूप से मिट्टी और मुरूम का काला कारोबार कर रहे दो भारी वाहनों को रंगे हाथों दबोच लिया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से अवैध परिवहन में लगे सिंडिकेट के बीच अफरा-तफरी का माहौल है।

जांच दल को देख उड़े होश, नहीं दिखा पाए कागज़

खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रभारी खनिज निरीक्षक समयलाल गुप्ता और उनकी टीम ने ब्यौहारी के रेलवे तिराहा के पास घेराबंदी की। इस दौरान टीम ने एक हाइवा क्रमांक एमपी 04एचई 2576 और एक बिना नंबर के नीले रंग के स्वराज ट्रैक्टर को रोका। जब टीम ने इनसे परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज और अनुमति पत्र मांगे, तो वाहन चालकों के पास सिवाय बहानों के और कुछ नहीं था। बिना अनुमति और रॉयल्टी चोरी कर ले जाई जा रही इस खनिज संपदा को टीम ने तत्काल अपनी कस्टडी में ले लिया।

थाने में कैद हुए माफिया के वाहन

पकड़े गए दोनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षा के मद्देनजर ब्यौहारी थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया है। खनिज विभाग ने मध्य प्रदेश खनिज नियमों के तहत कड़ा मामला दर्ज कर आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह तो सिर्फ झांकी है, आने वाले दिनों में अवैध उत्खनन के मुख्य अड्डों पर भी बड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

चोरी की छूट अब बीते दिनों की बात

खनिज विभाग के अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि शहडोल की धरती का सीना चीरकर अवैध कमाई करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि खनिज से जुड़ा कोई भी कार्य केवल वैध अनुमति के साथ ही किया जाए, अन्यथा जेल की सलाखें और भारी जुर्माना माफियाओं का इंतजार कर रहा है।

रेलवे मजदूर कांग्रेस ने किया नए विद्युत अभियंता का स्वागत

समस्याओं के समाधान की जताई उम्मीद

शहडोल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बिलासपुर मंडल के नव-पदस्थ वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता वासु गुप्ता का कार्यभार ग्रहण करने पर भव्य स्वागत किया। बिलासपुर मंडल समन्वय कक्ष के सामने हुई इस औपचारिक मुलाकात में संगठन के दिग्गज नेताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दीं। मंडल समन्वयक विजय अग्निहोत्री और जोनल कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव ने आशा व्यक्त की कि श्री गुप्ता के आने से रेल कॉलोनियों के आधुनिकीकरण, बिजली मीटरों की सटीक रीडिंग और विद्युत सामग्री की किल्लत जैसी पुरानी समस्याओं का अंत होगा। पूर्व में शहडोल और बिलासपुर में अपनी सेवाएं दे चुके वासु गुप्ता से रेल कर्मियों को विकास कार्यों में तेजी लाने की बड़ी अपेक्षाएं हैं।

एसईसीएल प्रबंधन को कलेक्टर की दो टूक

जमीन गई तो नौकरी और मुआवजा दो, किसानों को गुमराह करना बंद करो

शहडोल। रामपुर बट्टरा खुली खदान परियोजना से प्रभावित किसानों के आर-पार के संघर्ष और 16 मार्च से खदान ठप्प करने की चेतावनी ने शासन-प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए हैं। शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. केदार सिंह स्वयं एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के विश्राम गृह पहुंचे, जहां कोयला अधिकारियों और आक्रोशित किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैठक में कलेक्टर का रुख बेहद कड़ा रहा, जहां उन्होंने किसानों के हक को लेकर एसईसीएल प्रबंधन की जमकर क्लास ली।

बोर्ड की बैठक में मैं खुद आऊंगा

बैठक की शुरुआत में ही कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने रोजगार और मुआवजे की फाइलें लटकने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब किसानों की जमीन ले ली गई है, तो नौकरी और मुआवजे के भुगतान में इतनी देरी क्यों? उन्होंने प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों के हितों के लिए यदि कानून और बोर्ड के नियमों में संशोधन की जरूरत है, तो वह भी किया जाए। कलेक्टर ने यहाँ तक कहा कि बिलासपुर मुख्यालय में होने वाली बोर्ड की बैठकों में मुझे बुलाया जाए, मैं स्वयं किसानों के पक्ष में प्रस्ताव रखूंगा।

आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा प्रबंधन

बैठक में किसानों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा ने प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कलेक्टर के सामने ही एसईसीएल अधिकारियों को आगाह किया कि वे जिला प्रशासन को गुमराह करना बंद करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रबंधन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट न तो न्यायसंगत है और न ही धरातल के सच के करीब। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर गोलमोल जवाब का यही सिलसिला रहा, तो 16 मार्च से खदान का चक्का जाम होना निश्चित है।

जनप्रतिनिधियों के बागी तेवर

पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ने बैठक को केवल सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा बताते हुए कहा कि ऐसी बैठकों का कोई मतलब नहीं, जब तक ठोस परिणाम न निकले। वहीं, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शांति मनमोहन चौधरी ने इसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई करार देते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, खदान बंद रहेगी। किसान नेता आदित्य त्रिपाठी, राजकमल मिश्रा और ओमप्रकाश द्विवेदी सहित कई सरपंचों ने एकमत होकर खदान बंदी के प्रस्ताव पर सहमति जताई।

कलेक्टर का आश्वासन, पर किसान अड़े

कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि वे अब हर सप्ताह एक-एक गांव की अधिग्रहण संबंधी समस्याओं की समीक्षा करेंगे। हालांकि, किसान अब ठोस आदेश के बिना पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बैठक में बिलासपुर मुख्यालय से आए महाप्रबंधक और सोहागपुर क्षेत्र के अधिकारियों की चुप्पी ने किसानों के गुस्से को और भड़का दिया है। अब सभी की नजरें 16 मार्च पर टिकी हैं, जब किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए खदान की तालाबंदी करेंगे।

खबर संक्षेप

17 मार्च तक सुरक्षा जवान एवं सुपरवाईजर के लिए पंजीयन शिविर

उमरिया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा जवान एवं सुपरवाईजर के लिए पंजीयन शिविर का आयोजन 17 मार्च तक किया जाना है । उन्होने बताया कि 16 मार्च को शासकीय आईटीआई पाली में तथा 17 मार्च को शासकीय आईटीआई उमरिया में पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे । उन्होने कहा है कि शिविर पंजीयन करते समय आवेदको से किसी भी प्रकार का शुल्क न वसूला जाए । शिविर पूरी तरह निःशुल्क रहेगा ।

पाली में मूंगफली बीज का किया गया वितरण

उमरिया। उप संचालक कृषि संग्राम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना अंतर्गत मिशन राष्ट्रीय तिलहन योजना के तहत मूंगफली बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन विकासखंड पाली में किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 20 किसानों को मूंगफली बीज किस्म जी जी 37 वितरण किया गया। ब्लॉक एस. ए. डी. ओ. सूरज सिंह आर्मो, सुश्री शान्ति सिंह कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय शाहपुर, एवं दिलीप कुमार पाठक (प्रोजेक्ट एसोसिएट, एफ.पी.ओ., बाधवगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी) की उपस्थिति रही। दूरांचल क्षेत्रों से आए कृषक कुशम्हाकला, मालाचुआ, ओढ़ेरा, खोलखमरा, चाका, हाथपुरा, ग्रामों के किसानों ने योजना का लाभ प्राप्त किया ।

वसूली कार्य में लापरवाही दो राजस्व कर्मी निलंबित

कटनी। निगम के बकाया करों की वसूली हेतु आयोजित होने वाले विशेष वसूली शिविर के दौरान वसूली कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन का दोषी मानते हुए निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने नगर निगम के दो सहायक राजस्व निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

फाइलों में बह रही विकास की गंगा, धरातल पर सिसकती जनता

बुढ़ार जनपद में भ्रष्टाचार का शुक्ला काल

शहडोल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का नारा बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ जिले का बुढ़ार जनपद सरकारी खजाने की लूट का कुरुक्षेत्र बन चुका है। यहां विकास की इबारत ईंट-गारे से नहीं, बल्कि कमीशनखोरी की स्याही से लिखी जा रही है। बुढ़ार जनपद की पांच पंचायतों सिंधली, बोकरामार, कुडेली, बहगढ़ और ढोलकू में भ्रष्टाचार का खुला-खेल चल रहा है, जिसे देखकर व्यवस्था भी शर्मसार हो जाए। यहां विकास कार्य जमीन पर उतरने से पहले ही फाइलों के जरिए साहबों की तिजोरियों में दम तोड़ देते हैं।

अरिहंत विहार का व्हाइट हाउस

जनपद मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित अरिहंत विहार कॉलोनी का एक आलीशान बंगला इन दिनों चर्चाओं के केंद्र में है। आरोप है कि यह बंगला विकास का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का कंट्रोल रूम है। यहां पदस्थ संविदा उपयंत्री अनिल शुक्ला, जिन्हें क्षेत्र में भ्रष्टाचार का महागुरु कहा जाने लगा है, इसी बंगले से पंचायतों का रिमोट कंट्रोल चलाते हैं। सूत्रों का दावा है कि शुक्ला जी को फील्ड पर जाने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। पंचायत सचिवों के साथ मिलकर फाइलों का ऐसा मायाजाल बुना जाता है कि बिना एक पत्थर हिले ही लाखों-करोड़ों का भुगतान बंदरबांट कर लिया जाता है। धरातल पर जनता धूल फांक रही है, कीचड़ में चलने को मजबूर है, लेकिन उपयंत्री महोदय के घर में नोटों की बारिश हो रही है।

संविदा की सैलरी और करोड़ों का साम्राज्य

एक संविदा कर्मचारी, जिसकी आधिकारिक पगार मुश्किल से घर चलाने लायक होती है, उसके पास कुबेर का खजाना कहाँ से आया? यह सवाल आज पूरे जिले की जुबान पर है। अरिहंत विहार में करोड़ों की लागत से बना महलनुमा घर, लग्जरी चार पहिया गाडिय़ां और दोपहिया वाहनों का

काफिला। चर्चा है कि रीवा और सतना जैसे बड़े शहरों में शुक्ला ने बेनामी जमीन और रियल एस्टेट में करोड़ों का निवेश कर रखा है। घर के भीतर बेशकीमती आभूषणों और बैंक बैलेंस का अंबार लगा है। यदि लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू निष्पक्ष तरीके से आय से अधिक संपत्ति की जांच कर ले, तो बुढ़ार का यह छोटा सा संविदा कर्मचारी जिले का सबसे बड़ा सफेदपोश कुबेर निकल सकता है।

सी.ई.ओ. की मौन स्वीकृति या लाचारी

इस पूरे गोरखधंधे में जनपद सीईओ की भूमिका पर भी गंभीर सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या साहब को अपने नाक के नीचे हो रहे इस खुले भ्रष्टाचार की भनक नहीं है? या फिर हिस्सेदारी की डोर इतनी मजबूत है कि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है? ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि सीईओ साहब को एसी दफ्तरों से निकलकर पंचायतों का भौतिक सत्यापन करने की फुर्सत नहीं है। जनता की शिकायतों को रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया जाता है, जिससे इन भ्रष्टाचारियों के हौसले हिमालय से भी ऊंचे हो गए हैं।

पंचायतों में कागजी विकास का मॉडल सिंधली से लेकर ढोलकू तक, हर पंचायत में एक ही कहानी है। कागजों पर मजदूर काम कर रहे हैं, पर असल में मशीनें चल रही हैं या काम हुआ ही नहीं। जो थोडा-बहुत काम दिखावे के लिए हुआ है, वह पहली बारिश भी नहीं झेल पाएगा। हर फाइल पर चढ़ावे की दर तय है, जिसके बिना एक पैसा भी आगे नहीं बढ़ता।

लोकायुक्त और सीबीआई तक पहुंची गूंज

अब यह मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जागरूक नागरिकों और ग्रामीणों ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। खबर है कि अनिल शुक्ला और उनके सहयोगियों की कुंडली मुख्यमंत्री कार्यालय, आयकर विभाग, लोकायुक्त और सीबीआई तक भेज दी गई है। मांग की गई है कि एक विशेष जांच दल गठित कर पंचायतों में हुए कार्यों का डिजिटल और भौतिक सत्यापन कराया जाए।

प्रशासन के लिए अग्निपरीक्षा

जिला प्रशासन की साख आज दांव पर है, एक तरफ सरकार की छवि है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का यह घुन। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषी उपयंत्री और उनके मददगारों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे।

प्रधानमंत्री ने असम से किसानों के खाते में अंतरित की पीएम किसान सम्मान निधि की राशि

उमरिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य से 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के खाते में 18 हजार 640 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। उमरिया जिले के 93535 किसानों के खाते में 187070000 रुपये की राशि अंतरित हुई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्टर सभागार उमरिया में देखा गया। इस अवसर पर कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन , अधिक्षक भू अभिलेख सतीश सोनी,तहसीलदार दिलीप सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के खातों मे राशि अंतरित की

उमरिया जिले कि 108009 महिलाओं के खातों में राशि हुई अंतरित

उमरिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने ग्वालियर के घाटीगांव से प्रदेश कि 1.25 करोड से अधिक महिलाओं के खाते में 1836 करोड रूपये की राशि अंतरित कि जिले कि 108009 महिलाओ के खाते में की राशि अंतरित हुई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उमरिया जिले कि समस्त आंगनबाडी केंद्रो में देखा एवं सुना गया। इस अवसर पर आंगनबाडी केंद्रो में बडी संख्या में आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, लाडली बहनें उपस्थित रही।

नेशनल लोक अदालत में पति-पत्नी के बीच सुलह से पुनः दाम्पत्य जीवन की शुरुआतः एक अद्भुत न्यायिक प्रयास

कोतमा। 14 मार्च को न्यायालय परिसर मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गंगाचरण दुबे के खण्डपीठ क0-9 में तब एक रोचक दृश्य उत्पन्न हुआ, जब न्यायाधीश ने तलाक लेने आये पति-पत्नी के मध्य सुलह करा दी और पति-पत्नी परिवार सहित लोक अदालत से पुनः दाम्पत्य जीवन के निर्वाह हेतु वापस लौट गये। प्रकरण अनुसार पत्नी सुनीता चौधरी (परिवर्तित नाम) पति विकम लाल चौधरी का विवाह 24 अप्रैल. 2012 को कोतमा में संपन्न हुआ था, दोनो दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहे थे, उनके संसर्ग से चार संताने तीन पुत्री एवं एक पुत्र उत्पन्न हुआ लेकिन पति के संदेह जनक व्यवहार, शराब पीकर घरेलू हिंसा कारित करने तथा पत्नी द्वारा पति का अनादर किये जाने के आरोप-प्रत्यारोपों के मध्य उनके बीच कटुता उत्पन्न हो गई और पत्नी दो वर्ष पूर्व पति और बच्चों को छोडकर पृथक निवास करने लगी तथा उनके मध्य दाम्पत्य संबंध समाप्त हो गये, जब पति द्वारा पत्नी का उचित देखरेख नही की गई और ध्यान नही रखा गया तो पत्नी ने विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की, पति ने भी विवाह विच्छेह हेतु सहमति दर्शायी तथा प्रारंभिक कथन अंकित कराये, किंतु न्यायालय द्वारा अंतिम कथन और लोक अदालत के प्रकरण पर पुनः एक बार सुलह का प्रयास किया गया, यह प्रयास रंग लाया और पत्नी की माँ तथा पति की मॉ एवं परिजनों के मध्य उभयपक्षों के मध्य पुनः समझौता हो गया और वे दोनो प्रसन्नतापूर्वक दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु तैयार हो गये। पक्षकारों ने नवीन जीवन के शुरूआत के लिए न्यायाधीश से प्रार्थना की कि उनके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाकर प्रदान किया जावे ताकि वे न्यायालय के समक्ष किये गये संकल्पों को जीवनभर याद रख सकें। पक्षकारों की इच्छापूर्ति के लिए फोटोचित्र खिंचवाकर प्रदान किया गया, पक्षकारों एवं परिजनों द्वारा आभार व्यक्त किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमडी पटेल और खण्डपीठ सदस्य राखी चर्मकार एवं अनेक अधिवक्ता इस अवसर पर न्यायालय में मौजूद थे।

एसोसिएशन ऑफ वी क्लब ऑफ इंडिया सत्र 2025-26 की आधिकारिक यात्रा संपन्न

कोतमा। वी क्लब निस्वार्थ कोतमा के तत्वाधान में शनिवार को राधिका होटल में एसोसिएशन ऑफ वी क्लब ऑफ इंडिया सत्र 2025-26 की आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वी मनीषा सोनी, विशिष्ट अतिथि भूतपूर्व जिला प्रेसिडेंट वी अनीता फरमानिया की उपस्थिति रही। साल भर होने वाली गतिविधियों का विवरण बताया गया मंच का संचालन क्लब सचिव वी डॉक्टर संगीता प्रजापति द्वारा किया गया। एरिया ऑफिसर वी रचना जैन द्वारा एरिया की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में मीडिया कर्मी भरत मिश्रा का सम्मान किया गया और एक सेवा गतिविधि के रूप में गरीबों को अन्य दान किया गया। वी क्लब कोतमा की अध्यक्ष वी मोहिनी वर्मा द्वारा कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में एरिया सचिव वी शिल्पा जैन, पूर्व अध्यक्ष वी किरण गोयनका, वी रीता गुप्ता, वी निशा, वी सुमन वर्षा, वी छाया, वी आरती गुप्ता, वी ममता, वी निशा अग्रवाल, वी रजनी खटोल, वी वर्षा चावड़ा की उपस्थिति रही।

अनूपपुर जिले के 91675 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि हुई जारी

पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम

अनूपपुर। कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुवाहाटी, असम में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं किसानों द्वारा देखा एवं सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुवाहाटी, असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22 वीं किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से देशभर के किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। इसी क्रम में अनूपपुर जिले के 91,675 किसानों के बैंक खातों में भी सम्मान निधि की राशि सीधे अंतरित की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सिंह, अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर कमलेश पुरी, अधीक्षक भू-अभिलेख प्रदीप कुमार मोगरे सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

दिव्यांग बच्चों के भविष्य को संवारने जिला प्रशासन की पहल

18 मार्च को अनूपपुर में विशेष स्क्रीनिंग एवं प्रमाणन शिविर

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार जिले में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की पहचान, स्क्रीनिंग और दिव्यांगता प्रमाणन के लिए 18 मार्च 2026 को जिला स्तरीय विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर जिला चिकित्सालय अनूपपुर के स्व-सहायता भवन में प्रातः 11:00 बजे से प्रारंभ होगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्देश्य जिले के दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा एवं प्रमाणन उपलब्ध कराना है। इस बार केवल 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों ही नहीं, बल्कि कम प्रतिशत दिव्यांगता वाले बच्चों की भी पहचान की जाएगी, ताकि समय रहते उपचार सुनिश्चित किया जा सके। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. आर. परस्ते, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. जनक सारीवान, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. एन.पी. मांझी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमार बच्चों का परीक्षण करेंगे। शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला मेडिकल बोर्ड दिव्यांगता का आकलन कर पोर्टल पर डेटा अपलोड करेंगे तथा प्रमाणन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। जिन बच्चों के पास अभी तक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले दिव्यांग बच्चों को शिविर स्थल तक लाने और वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत समन्वयक और नगरीय निकायों की होगी। बच्चों के साथ एक अभिभावक भी आ सकेंगे। नगरपालिका अनूपपुर को शिविर स्थल पर टेंट, पेयजल, भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। साथ ही सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूल प्रबंधन समितियों और मैदानी अमले के माध्यम से इस शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि जिले का हर पात्र बच्चा इस शिविर का लाभ प्राप्त कर सके।

अब कोयला अधिकारियों का पदोन्नति के साथ तबादला अनिवार्य

ई-5 से ई-6 के कोयला अधिकारियों पर लागू होगा नया नियम

राजनगर। कोल इंडिया कंपनी में 1954 की संख्या में ऐसे अधिकारी हैं तो एक ही इकाई में 15 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं। इनमें एसईसीएल में 451, बीसीसीएल में 191, सीसीएल में 250, इसीएल में 201. एमसीएल में 216, एनसीएल में 147, एनईसी में 7, डब्ल्यूसीएल में 352 है। कोलइंडिया द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब ई-5 से ई-6 ग्रेड के पदोन्नति पाने वाले कोयला अधिकारियों का एक अनुषंगी कंपनी से दूसरी अनुषंगी कंपनी में तबादला करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अनुरोध के आधार पर तबादला लेने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं किया है। उन्हें उसी कंपनी में पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है। उल्लेखनीय है, कि कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने एग्जिक्यूटिव जॉब रोटेशन व ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। जारी कार्यालय आदेश के अनुसार पदोन्नति के साथ होने वाले तबादलों और अधिकारियों को अस्थायी रूप से रोकने के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधान के तहत ई-5 से ई-6 विस्तार दिया जाएगा। ग्रेड में पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों का एक सहायक कंपनी से दूसरी सहायक कंपनी में तबादला अनिवार्य होगा। हालांकि जिन अधिकारियों ने अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर लिया है और अभी निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उन्हें अस्थायी रूप से वर्तमान कंपनी में पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है। तय अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से स्थानांतरित कंपनी में योगदान देना पड़ होगा। आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी सहायक कंपनी के सीएमडी को परिचालन जरूरतों को देखते हुए अधिकतम 5 प्रतिशत अधिकारियों को पदोन्नति के बाद अस्थायी रूप से रोकने का अधिकार होगा। यह रोक अधिकतम एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी को स्थानांतरित कंपनी में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। इस अवधि के बाद न तो और न ही पदोन्नति रद्द करने की अनुमति होगी।

खबर संक्षेप

रेलवे महाप्रबंधक ने कटनी पहुंचकर किया निरीक्षण

कटनी। शुक्रवार को पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक ने बीते दिनों एनकेजे क्षेत्र में मालगाड़ी के 4 डिब्बों के बेपटरी होने की घटना स्थल का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जबलपुर मंडल के एडीआरएम आनंद कुमार और रेलवे बोर्ड द्वारा गठित विशेष जांच समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हादसे के तकनीकी कारणों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एडीआरएम आनंद कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महाप्रबंधक का यह दौरा वैसे तो नियमित निरीक्षण का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने विशेष प्राथमिकता के साथ मालगाड़ी हादसे वाले स्थल का जायजा लिया। वर्तमान में हादसे की जांच एसएसई स्तर पर की जा रही है। वास्तविक कारणों का खुलासा पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। हादसे के तुरंत बाद युद्धस्तर पर किए गए मरम्मत कार्यों के चलते रेलवे ट्रैक को पहले ही बहाल कर दिया गया था।

बका लेकर घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार

कटनी। एन.के.जे. पुलिस ने एक युवक को बका लेकर घूमते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एन.के.जे. पुलिस को सूचना मिली थी कि जुहला नहर के पास लभेर के नीचे एक संदिग्ध व्यक्ति किसी धारदार हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना की तस्दीक करते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी। वहाँ जितेन्द्र तिवारी 36 वर्ष निवासी देवराखुर्द को संदिग्ध अवस्था में पाया गया। पुलिस ने जब आरोपी जितेन्द्र की तलाशी ली तो उसके पास से लोहे का 'बका' बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

संस्थानों में बाल श्रम नहीं कराने हेतु रैली निकाल किया जागरूक

कटनी। जिले में बाल श्रम के विरूद्ध जनजागरण अभियान के तहत कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र बरगवां में रैली निकाली गई। साथ ही पंपलेट, ब्रोसर एवं स्पीकर के माध्यम से सभी संस्थानों एवं नागरिकों को बाल श्रम न कराने हेतु प्रचार-प्रसार किया गया। रैली में श्रम पदाधिकारी के.बी. मिश्रा द्वारा बाल श्रम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संबध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिनियम के प्रावधानों अनुसार किसी भी संस्थान में बाल श्रम नियोजित किये जाने की स्थिति में नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास एवं रूपये 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। किसी भी संस्थान एवं उद्योग में 14 वर्ष या उससे कम की आयु के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही 14 वर्ष से 18 वर्ष के कुमार श्रमिकों का नियोजन खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में पूर्णः प्रतिबंधित है। रैली में श्रम पदाधिकारी के. बी. मिश्रा, श्रम निरीक्षक रमाकांत लोधी, लक्ष्मीकांत पटेल, मनोज कुमार यादव, विशेष पुलिस ईकाई की ओर से देवकी नंदन परौहा, जन साहस संस्था से मुकेश द्विवेदी एवं विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।

मां कर्मा जयंती मनाने एवं शोभायात्रा निकालने बैठक में बनाई रूपरेखा

सिलौंडी। सकल साहू समाज सिलोंडी एवं नेगाई में माता कर्मा के जन्म-महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 मार्च को शिव मंदिर झंडा चौक से नेगई निकलने वाली शोभायात्रा के संबंध में बैठक संपन्न की गई। बैठक में शोभायात्रा की रूपरेखा पर चर्चा हुई । बैठक में पूर्व मंत्री रविशंकर साहू की विशेष मौजूदगी रही। समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करने पर चर्चा हुई। इस दौरान वरिष्ठ युवा की विशेष मौजूदगी रही है।

जगमगा उठा मां काली मंदिर, 19 मार्च से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र

विलियस नंबर 1 में तैयारियां अंतिम चरण में, 13 मार्च की बैठक में कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां

धनपुरी। नगर के वार्ड नंबर 5 स्थित प्राचीन मां काली मंदिर विलियस नंबर 1 चैत्र नवरात्र पर्व को लेकर इन दिनों पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में रंगा नजर आ रहा है। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है, जिससे पूरा मंदिर जगमगा उठा है। सनातन धार्मिक समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 19 मार्च से प्रारंभ हो रहे चैत्र नवरात्र पर्व को श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ भव्य रूप में मनाने की तैयारियां की जा रही हैं।

13 मार्च को हुई बैठक, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

मां काली मंदिर सनातन धार्मिक समिति के अध्यक्ष एस.पी. सिंह ने बताया कि नवरात्र पर्व की तैयारियों को लेकर 13 मार्च को समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में समिति से जुड़े सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं, ताकि नवरात्र के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। समिति के सदस्य पूरे समर्पण और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं।

नौ दिनों तक होंगे धार्मिक अनुष्ठान

नवरात्र के नौ दिनों तक मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर में जवारा-कलश स्थापना, ज्योति कलश, तेल-घी सहित पूजा सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में रंगरोगन, साफ-सफाई, सजावट और श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। समिति के सदस्य लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं।

आस्था का प्रमुख केंद्र है मां काली मंदिर

धनपुरी का मां काली मंदिर विलियस नंबर 1 नगर का प्राचीन और आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और पूरे वर्ष यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। नवरात्र पर्व के दौरान यहां विशेष पूजा-अर्चना होती है और दूर-दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से मां काली के दर्शन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम

समिति के अध्यक्ष एस.पी. सिंह ने बताया कि नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। समिति से जुड़े सभी सदस्य मिलकर आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं।

परमात्मा को पाना है तो गुरु के चरणों में आना होगाः महंत अर्जुन दास

बुढार। नगर की हीरा कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ।
इस अवसर पर श्री राम जानकी मंदिर के महंत श्री श्री 1008 श्री अर्जुन दास महाराज का गरिमामई आगमन हुआ। महाराज श्री के सानिध्य में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को उनकी अमृतमयी वाणी से कथा श्रवण करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ।

गुरु और माता-पिता ही हैं ईश्वर का द्वार

अपने संबोधन में महाराज श्री ने भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करते हुए कहा किः ₹यदि आपको परमात्मा को पाना है या उनका होना है, तो सबसे पहले अपने गुरु और माता-पिता के श्री चरणों का होना पड़ेगा। समर्पण और सेवा के बिना ईश्वर

से मिलन का बोध संभव नहीं है।₹
उन्होंने आगे विस्तार देते हुए बताया कि भागवत प्राप्ति (ईश्वर की प्राप्ति) के लिए जीवन में प्रेम और भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वह भक्ति के मर्म को नहीं समझ सकता।

सुखदेव-परीक्षित संवाद का रसपान

कथा के मुख्य वक्ता श्री बालकृष्ण पांडे ने द्वितीय दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए शुकदेव और राजा परीक्षित के बीच हुए संवाद का मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक जिज्ञासु शिष्य और एक तत्वज्ञानी गुरु के मिलन से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कथा के दौरान भजनों पर श्रोता भावविभोर होकर झूमते नजर आए।
इस आध्यात्मिक आयोजन में कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु भक्ति रस का आनंद लेने पहुंच रहे हैं।

मानपुर एसडीएम की कार्रवाईः अवैध टपरे से 41 बोतल शराब जब्त, टपरा सील

उमरिया। मानपुर अनुविभागीय अधिकारी हरनीत कौर कलसी ने प्रशासनिक दल के साथ ग्राम गडरिया टोला में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोहे के टपरे एवं गुमटी को हटवाकर वहां से अवैध शराब की बोतलें जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान टपरे से कुल 41 बोतल शराब बरामद की गई, जिन्हें मौके पर अमरपुर चौकी प्रभारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दिया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गडरिया टोला में लोहे का टपरा और गुमटी बनाकर अवैध रूप से दुकान संचालित की जा रही थी। मौके पर जांच के दौरान वहां अंडा, मांस, शराब की बोतलें तथा बीयर पाई गई। उक्त दुकान आशीष सोनी

निवासी अमरपुर द्वारा संचालित की जा रही थी, जो कार्रवाई के दौरान मौके पर उपस्थित मिले।प्रशासनिक दल ने कार्रवाई करते हुए टपरे से पका हुआ मांस, भोजन सामग्री, फ्रिज, गैस सिलेंडर सहित अन्य उपयोगी सामान को बाहर निकलवाया। साथ ही वहां अवैध रूप से लिए गए बिजली कनेक्शन को भी तत्काल हटाया गया। एसडीएम हरनीत कौर कलसी के निर्देश पर अवैध रूप से स्थापित टपरे को सील कर दिया गया तथा संचालक को सख्त निर्देश दिए गए कि आगामी आदेश तक उक्त टपरे को नहीं खोला जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सील फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रस्फुटन समितियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम

उमरिया। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड करकेली जिला उमरिया के निर्देशानुसार नवांकुर संस्था सील फाउंडेशन द्वारा जिला समन्वयक रविन्द्र शुक्ल के मुख्यातिथ्य में सेक्टर करकेली व घुलघुली की प्रस्फुटन समितियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण श्शप्रस्फुटन शक्ति संचय अभियानश्श के तहत जनपद सभागार करकेली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यातिथि व उपस्थित सदस्यों का स्वागत अभिनन्दन कर किया गया।

प्रथम सत्र में सील फाउंडेशन अध्यक्ष दीपक नामदेव द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का परिचय देते हुए परिषद की रूपरेखा व अवधारणा के बारे में बताया गया। द्वितीय सत्र में सील फाउंडेशन सचिव संदीप शुक्ला द्वारा सृजन योजना व प्रस्फुटन योजना के बारे में बताते हुए, कार्य दायित्व के संबंध में बताया गया। तृतीय सत्र में जिला समन्वयक रविन्द्र शुक्ल द्वारा समितियों के दस्तावेजीकरण पर प्रकाश डालते हुए, दस्तावेज संधारण व कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। चतुर्थ सत्र में परामर्शदाता सोनाली तिवारी द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे बताया गया। पांचवे सत्र में सीएम सोशल इंटर्न रोशनी यादव द्वारा परिषद द्वारा संचालित सीएमसीएलडीपी पाठ्यक्रम के संबंध ने बताया गया। इसी तरह छठवें सत्र में दीपक नामदेव द्वारा एक्टिविटी के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं को बौद्धिक विकास पर चर्चा की गई व एमपीजेएपी एप्लिकेशन के बारे में बताया गया। अंतिम व समापन सत्र में प्रतिभागियों का फीडबैक लिया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने कहा कि आज का प्रशिक्षण उनके लिए अत्यंत उपयोगी व सार्थक है। प्रमोद सिंह ने कार्यशाला को लाभकारी बताया और जनसहयोग के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने व दस्तावेज संधारण की बात कही। अर्जुन सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वज हमें बचपन से समाज कार्य के लिए प्रेरित करते आए है, अब हम परिषद के साथ और अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। चंदेराम बैगा ने कहा कि यहां हमें स्थानीय लोगों के साथ आसानी से जुडने का तरीका मिला, जिससे हम अधिक लोगों से जुड़ पाएंगे । कार्यशाला में सेक्टर करकेली व घुलघुली के ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष, सचिव व सदस्य प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे।

सीएम के बरही प्रवास की तैयारियां पूर्ण, विधायक और कलेक्टर ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शनिवार 14 मार्च को प्रस्तावित बरही प्रवास के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक और कलेक्टर आशीष तिवारी ने शुक्रवार को बरही पहुंचकर कार्यक्रम स्थलों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी राकेश सिंह, जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र पटेल, नगर परिषद बरही के अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल और एसडीएम विवेक गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।विधायक और कलेक्टर ने श्री विजयनाथ धाम मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले कृषि सम्मेलन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री तिवारी ने पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभा स्थल में पूरी गंभीरता के साथ सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। कलेक्टर श्री तिवारी ने मंचीय व्यवस्था, बैठक दीर्घा और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए जाने वाले प्रदर्शनी स्टालों का भी जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरही परिसर में बनाए गए हेलीपैड स्थल का जायजा लिया गया। इसके पश्चात 'आभार रैली रोड-शो' के रूट का भौतिक सत्यापन किया गया। यह रोड-शो बड़ा तालाब से शुरू होकर सुभाष चौक, अमन बुक डिपो और कमानिया गेट से होते हुए विजयनाथ धाम मंदिर पहुंचेगा। कलेक्टर श्री तिवारी ने इस दौरान यातायात व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कलेक्टर ने बरही के बड़ा तालाब पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान बरही के बड़ा तालाब में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ भी करेंगे।

एसडीएम ने मैदानी कर्मियों को बैठक लेकर दिए निर्देश

मकान सूचीकरण का कार्य तीन दिन में करें पूरा

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जनगणना वर्ष 2027 के प्रथम चरण की तैयारी प्रशासनिक गलियारों में शुरू हो गई है। एसडीएम राकेश चौरसिया ने जनपद पंचायत के सभागार में जनगणना वर्ष 2027 के प्रथम चरण प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से मैदानी कर्मियों की मैराथन बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मैदानी कर्मियों को निर्देश दिए कि जन गणना के प्रथम चरण में मकानों की सूची करण का तत्काल शुरू करते हुए तीन दिवस के भीतर करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि जन गणना के कार्य के लिए शिक्षकों को प्रगणक बनाया जाएगा। एक प्रगणक एक ग्राम में सर्वे कार्य करेगा और 700 की आबादी पर एक प्रगणक घर घर जाकर भौतिक सत्यापन कर मोबाइल ऐप पर सेंसस मांनटिरिग एंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल डेटा संकलन का कार्य करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जन गणना से संबंधित अन्य जानकारी विस्तार से देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए की इस कार्य में किसी तरह कोई लापरवाही बरती गई तो संबंधित पर सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाएगा।
जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित बैठक में तहसीलदार आशीष अग्रवाल, सीईओ अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार राजकुमार नामदेव, पंचायत इंस्पेक्टर मोहन सिंह, पीसीओ, एडीओ सभी पंचायतों सचिव, रोजगार सहायक एवं हल्का पटवारी मौजूद रहे। विकासखण्ड क्षेत्र में बुधवार को जनगणना कार्य के लिए गुरुवार को दो चरणों में बैठक आयोजित की गई थी। पहली बैठक जनपद पंचायत के सभागार में जिसमें विकासखण्ड क्षेत्र की 54 ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायक, पटवारी तथा स्लीमनाबाद तहसील कार्यालय में आयोजित बैठक में 25 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं हल्का पटवारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि जनगणना के दौरान नागरिकों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें मकान सूची करण के तहत घर के संबंध में सात सवाल शामिल हैं, जैसे मकान नंबर, फर्श, दीवार और छत की सामग्री, उपयोग और स्थिति। पेयजल, प्रकाश, शौचालय, रसोईघर और परिवार की संख्या, मुखिया का नाम आदि।

न बजेगी शहनाई, न होंगे मांगलिक कार्य, आज से प्रारंभ होगा खरमास

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

सनातन कैलेंडर के अनुसार 15 मार्च से खरमास का आगाज हो जायेगा। इसके चलते फिर एक माह तक विवाह व अन्य शुभकार्य नहीं होंगे।इस दौरान विवाह,सगाई,यज्ञ, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नही होंगे। एक माह बाद जाकर 14 अप्रैल को खरमास का समापन होगा तब जाकर शुभ मांगलिक कार्य शुरू होंगे। अप्रेल से जुलाई तक रहेगी शादियों की धूम -खरमास के खत्म होते ही खुशियों का सीजन फिर से लौटेगा। 15 अप्रेल से शहनाईया बजनी शुरू हो जायेंगी। 15 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच कुल 29 जबरदस्त मुहूर्त निकल रहे हैं। 12 जुलाई के बाद 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। इसके बाद सीधे 20 नवंबर (देवउठनी एकादशी) से ही दुबारा मांगलिक कार्य शुरू होंगे।
पंडित दिलीप पौराणिक ने बताया कि जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते है तो उसके फलित होने के लिए गुरु का प्रबल होना जरूरी है।धनु एवम मीन बृहस्पति ग्रह की राशियां है। खरमास के समय सूर्य इन दोनो राशियों पर होते है,इसलिए शुभ कार्य नही होते।वर्ष भर में दो खरमास लगता है।एक खरमास मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच और दूसरा खरमास मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक होता है। इस समय सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व माना जाता है।खासतौर पर जिनकी कुंडली मे सूर्य की कमजोर स्थिति हो उन्हें खरमास के दौरान सूर्य उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों में खरमास का महीना शुभ नहीं माना गया है।इस अवधि में मांगलिक कार्य करना प्रतिबंधित है।
15 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026तक सूर्य, मीन राशि में होंगे। इसे मीन मलमास कहा जाता है। इस एक महीने की अवधि में शुभ संस्कार नहीं किए जाएंगे। लेकिन चैत्र नवरात्र पर खरमास का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 19 अप्रैल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगे।19 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की उपासना का पर्व शुरू हो जायेगा।नवरात्र की उपासना पर खरमास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

खबर संक्षेप

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के नेतृत्व में प्रस्फुटन समितियों का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण सम्पन्न

अनूपपुर। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत विकासखंड जैतहरी के सेक्टर क्रमांक 05 में 14 मार्च को ग्राम पंचायत बरबसपुर में प्रस्फुटन समितियों का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन नवांकुर संस्था शिव मारुति युवा संगठन समिति के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवांकुर संस्था के अध्यक्ष बृजेश राठौर ने की। प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षक के रूप में रमेश द्विवेदी एवं परामर्शदाता अनिल सिंह परिहार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ की गई। प्रथम सत्र में नवांकुर सचिव बृजेश राठौर ने जन अभियान परिषद के उद्देश्यों एवं कार्यों का विस्तृत परिचय देते हुए प्रस्फुटन, नवांकुर एवं सृजन योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके पश्चात जैतहरी ब्लॉक समन्वयक फते सिंह ने प्रस्फुटन समिति के गठन, कार्यप्रणाली एवं रिकॉर्ड संधारण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में समितियों की सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। परामर्शदाता अनिल सिंह परिहार ने सीएमसीएलडीपी पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह पाठ्यक्रम शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व विकसित करने के लिए युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने उपस्थित सदस्यों को मार्गदर्शन देते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा और निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के समापन सत्र में प्रतिभागियों ने अपने प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान प्रशिक्षकों से प्राप्त किया।

नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन

अनूपपुर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर श्रीमती माया विश्वलाल के मार्गदर्शन में 14 मार्च, को जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय कोतमा राजेन्द्रग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय अनूपपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल के द्वारा, माँ सरस्वती के चित्र में पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मनोज कुमार लढ़िया, प्रथम जिला न्यायाधीश संयोजक नेशनल लोक अदालत नरेन्द्र पटेल, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती चैनवती ताराम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार वर्मा, सुश्री सुधा पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बॉबी सोनकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री सृष्टि साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटेल, जिला अधिवक्ता बार संघ से अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार, सचिव राम कुमार राठौर, शासकीय अभिभाषक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा, लीगल एड डिफेंस काउंसेल संतदास नापित, जिला अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्तागण खण्डपीठ के सुलहकर्ता सदस्यगण, पैरालीगल वालेंटियर्स, पुलिस बल, बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग, जिला न्यायालय एवं जिला प्राधिकरण अनूपपर के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहें। उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर 08 खण्डपीठ, तहसील सिविल न्यायालय कोतमा हेतु 04 खण्डपीठ एवं राजेन्द्रग्राम हेतु 03 खण्डपीठ का गठन किया गया। इस प्रकार जिले में कुल 15 खण्डपीठों का गठन किया गया। नेशनल लोक अदालत में दोपहर 02:00 बजे तक की स्थिति में आपराधिक 115, चैक बाउंस 20, क्लेम प्रकरण 05, वैवाहिक प्रकरण 15, विद्युत प्रकरण 50, अन्य सिविल प्रकरण 11 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 205, इस प्रकार कुल 421 प्रकरणों का निराकरण किया गया। एवं समस्त न्यायालयों की कार्यवाही जारी है।

विवाह करने के उद्देश्य से युवती का फिल्मी अंदाज में किया अपहरण

इंस्टाग्राम की दोस्ती बनी जी का जंजाल

काली स्कॉर्पियो में 3 दोस्तों का काला कारनामा

अनूपपुर। अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र में युवती के अपहरण के मामले में पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अपनी कार्यवाही शुरू की मामला संगीन और अपहरण से जुड़े होने के नाते पुलिस ने अपना समय न गवाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवती को जबरन स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर विवाह के उद्देश्य से अपहरण किया था। पुलिस ने वाहन भी जब्त कर लिया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया है।दरअसल यह पूरा मामला अनूपपुर जिले के थाना जैतहरी क्षेत्र का है जहां पर युवती के अपहरण के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। 13 मार्च 2026 को पीड़ति द्वारा थाना जैतहरी में लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया कि जयप्रकाश राठौर नामक युवक ने उसे जबरन स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर विवाह के उद्देश्य से अपहरण कर लिया। पीड़ति ने बताया कि वह शहडोल के एक पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती है। लगभग तीन वर्ष पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से जयप्रकाश राठौर से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवती ने स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने माता-पिता की इच्छा के अनुसार ही विवाह करेगी, घटना वाले दिन युवती अपनी सहेली के साथ घर के बाहर बैठी थी, तभी आरोपी काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन से वहां पहुंचा और चेहरे को साफे से ढककर युवती को जबरन वाहन में बैठाकर ले गया, वाहन में चालक सहित एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पीछा शुरू किया।

पीछा करने पर पिपरिया में छोड़कर भागा आरोपी

पुलिस की सक्रियता के कारण आरोपी जयप्रकाश राठौर ने पिपरिया क्षेत्र में युवती को छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया, घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और युवती के परिजन मौके पर पहुंचे, युवती के भाई और मामा ने उसे सुरक्षित वापस घर पहुंचाया, इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी और विभिन्न स्थानों पर दबिश दी, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की गई रही है।

स्कॉर्पियो वाहन सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

जैतहरी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 12 घंटे के भीतर अपहरण में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में जयप्रकाश राठौर (23 वर्ष) निवासी चोरभठी थाना जैतहरी, शुभम राठौर (23 वर्ष) निवासी बेला थाना अनूपपुर और सागर पटेल (22 वर्ष) निवासी मौहरी थाना कोतवाली अनूपपुर शामिल हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक एमपी 65 जेडबी 4472 को भी जब्त कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायालय अनूपपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी जैतहरी निरीक्षक अमर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टीम में उप निरीक्षक अमर लाल यादव, उप निरीक्षक जे.पी.एच. तिर्की, सहायक उप निरीक्षक विनोद विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक राजकुमार मार्को, संतोष जायसवाल, विजयानंद पांडे, श्रीश्याम शुक्ला तथा आरक्षक मनीष सिंह तोमर और विजय प्रताप सिंह शामिल रहे। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर और एसडीओपी पुष्पराजगढ़ के मार्गदर्शन में की गई है।

8-9 साल से अधूरा फ्लाईओवर, कब मिलेगी शहर को राहत?

चुनावी मझधार में फंसा अनूपपुर का पुल

अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर शहर को दो हिस्सों में जोड़ने वाला फ्लाईओवर ब्रिज पिछले 8-9 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन अब भी पूरा होने का इंतजार जारी है। कई बार भूमिपूजन और निरीक्षण के बावजूद काम की रफ्तार बेहद धीमी है। हालात ऐसे हैं कि अब लोगों को आशंका है कि यह परियोजना चुनावी मझधार में फंसकर और लंबा खिंच सकती है। जिला मुख्यालय शहर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज अब विकास से ज्यादा प्रतीक्षा और निराशा का प्रतीक बनता जा रहा है। लगभग एक दशक से चल रहे इस निर्माण कार्य को लेकर समय-समय पर कई घोषणाएं और भूमिपूजन हुए, लेकिन जमीनी हकीकत में काम की गति बेहद धीमी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होने में अभी और लंबा समय लग सकता है। शहर के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन के कारण ट्रैफिक जाम और आवागमन की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए फ्लाईओवर परियोजना शुरू की गई थी। हालांकि अब हालात यह हैं कि पुल निर्माण के चलते शहर के एक हिस्से का बाजार सिमट गया है जबकि दूसरी ओर का बाजार नए रूप में विकसित हो गया है। इस बीच कई विभागों के बीच समन्वय की कमी भी काम की धीमी गति का बड़ा कारण बनती नजर आ रही है।

निरीक्षण में सामने आई धीमी प्रगति

जिला विकास मंच के संयोजक वासुदेव चटर्जी और जागरूक नागरिक अरविंद बियानी ने हाल ही में फ्लाईओवर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कम संख्या में श्रमिक काम करते नजर आए, उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई तो 2027 के अंत तक भी पुल का निर्माण पूरा होना मुश्किल हो सकता है।

रेलवे और सेतु निगम के बीच समन्वय की कमी

फ्लाईओवर निर्माण में भारतीय रेल और सेतु निगम दोनों विभागों की भूमिका है। रेलवे ने पुल के गर्डर डालने का काम तो कर दिया, लेकिन उसके बाद कई सपोर्टिंग पिलर अभी भी रास्ते में पड़े हैं। इससे निर्माण कार्य और यातायात दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

विभागीय बाधाओं से अटका काम

निर्माण कार्य में कई अन्य विभागों की भी भूमिका है। रेलवे के पुराने क्वार्टर अभी तक नहीं हटाए गए हैं, जबकि विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे शिफ्ट करने हैं। इसके अलावा नगर पालिका की पाइपलाइन भी अब तक स्थानांतरित नहीं हुई है। इन सभी कारणों से निर्माण कार्य बार-बार बाधित हो रहा है।

रिटेनिंग वॉल और फिलिंग का काम अधूरा

फिलहाल फ्लाईओवर के एक हिस्से में रिटेनिंग वॉल के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ है, जबकि दूसरी ओर फिलिंग का काम अधूरा पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार फ्लाई ऐश और मिट्टी भराई का काम भी धीमी गति से चल रहा है, जिससे परियोजना की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है।

प्रशासन की सख्ती से ही मिल सकती है रफ्तार

स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि जिला प्रशासन सभी संबंधित विभागों को समय सीमा तय कर निर्देश दे तो निर्माण कार्य को गति मिल सकती है। कलेक्टर स्तर पर नियमित निरीक्षण और समन्वय बैठक होने से रेलवे, बिजली विभाग, नगर पालिका और अन्य एजेंसियों के लंबित कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं। तभी अनूपपुर शहर को इस फ्लाईओवर का वास्तविक लाभ मिल पाएगा।

अनूपपुर (बदरा) जनपद पंचायत में धुंधले बिलों का महाघोटाला

क्या सीईओ की आँखों पर बंधी है भ्रष्टाचार की पट्टी?

बदरा/जमुना। अनूपपुर: जिले की जनपद पंचायत बदरा इन दिनों भ्रष्टाचार की एक नई और शातिर प्रयोगशाला बन गई है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और लीकेज रोकने के लिए शासन द्वारा बनाए गए 'पंचायत दर्पण' पोर्टल का इस्तेमाल अब भ्रष्टाचारियों द्वारा अपने सुबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है। बदरा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खजाने की खुलेआम लूट हो रही है, और इसका जरिया बने हैं 'धुंधले बिल'।

सीईओ की कार्यप्रणाली पर उठ रहे गंभीर सवाल

इस पूरे सुनियोजित घोटाले में सबसे बड़ा सवाल जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भूमिका पर खड़ा हो रहा है। एक सीईओ के कंधों पर जनपद के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की सीधी निगरानी, बिलों के भौतिक सत्यापन और वित्तीय कार्यों की पारदर्शी समीक्षा की अहम जिम्मेदारी होती है।

यहाँ उठते हैं बड़े सवाल

बिना जांच के कैसे पास हो रहे बिल? यदि पोर्टल पर लगातार धुंधले और अपठनीय बिल अपलोड हो रहे हैं, तो सीईओ कार्यालय द्वारा उन्हें बिना सत्यापन के वित्तीय स्वीकृति कैसे दी जा रही है? क्या यह 'मौन स्वीकृति' है? क्षेत्र के जागरूक नागरिकों का सीधा आरोप है कि बिना उच्चाधिकारियों के संरक्षण या 'मौन स्वीकृति' के पंचायत स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गबन संभव ही नहीं है। इस घोर लापरवाही ने सीईओ की कार्यप्रणाली और उनकी सत्यनिष्ठा को पूरी तरह संदेह के घेरे में ला दिया है।

पंचायत दर्पण पोर्टल पर जानबूझकर अपलोड हो रहे अपठनीय और धुंधले बिल

क्या है भ्रष्टाचार का यह नया 'मोडस ऑपरेंडी'?

सूत्रों और पंचायत दर्पण पोर्टल की पड़ताल से एक बेहद चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्राम पंचायतों द्वारा पोर्टल पर सामग्री खरीदी और निर्माण कार्यों के बिल तो अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक सोची-समझी साजिश के तहत इतना 'धुंधला' कर दिया जाता है कि उनमें लिखी गई कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से पढ़ी ही न जा सके।

जनता में भारी आक्रोश, उच्च स्तरीय जांच की मांग

इस 'धुंधले घोटाले' के सामने आने के बाद बदरा क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। पंचायत के पैसों की इस बंदरबांट को लेकर नागरिकों ने जिला कलेक्टर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। 'पंचायत दर्पण' पोर्टल पर बदरा जनपद के तहत अपलोड किए गए सभी संदिग्ध और धुंधले बिलों की एक उच्च स्तरीय समिति (जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों) से जांच कराई जाए और मौके पर जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन हो। इस कृत्य में संलिप्त पंचायत सचिवों, सरपंचों और बिना देखे बिल पास करने वाले अधिकारियों) पर गबन का आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

जानकारी छिपाने की यह है साजिश

इन धुंधले बिलों को देखकर यह पता लगाना नामुमकिन है कि निर्माण सामग्री किस फर्म या दुकान से खरीदी गई है। बिल में सामग्री की मात्रा क्या है और किस दर पर खरीदी गई है, यह सब धुंधलेपन के पीछे छिपा दिया जाता है। बिल पर तारीख तक स्पष्ट नहीं होती, जिससे एक ही बिल को बार-बार इस्तेमाल करने की आशंका बढ़ जाती है। इस तकनीकी खेल के जरिए बिना वास्तविक काम किए या बेहद घटिया सामग्री का उपयोग करके लाखों रुपये के फर्जी बिल आसानी से पास कराए जा रहे हैं।

अनूपपुर जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान जारी

अब तक 638 किशोरियों को लगा सुरक्षा कवच

अनूपपुर। जिले में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 638 किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। कलेक्टर हर्षल पंचोली एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी के निर्देशन में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलका तिवारी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलेभर में टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान के तहत 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी तथा 15 वर्ष 3 माह तक की बालिकाएं टीकाकरण के लिए पात्र हैं। इसके अलावा अभियान शुरू होने के 90 दिनों के भीतर 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाली बालिकाओं को भी पात्र माना गया है। टीका 0.5 मिलीलीटर की एकल खुराक के रूप में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से दिया जा रहा है। यह टीकाकरण पूरी तरह स्वैच्छिक है तथा इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। यह सुविधा जिले के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है, जिनमें जिला चिकित्सालय अनूपपुर, सीएचसी कोतमा, जैतहरी, राजेंद्रग्राम, फुनगा, परासी, अमरकंटक तथा पीएचसी बिजुरी और बेनीबारी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक जिला चिकित्सालय अनूपपुर में 185, सीएचसी राजेंद्रग्राम में 106, सीएचसी कोतमा में 101, सीएचसी जैतहरी में 95, सीएचसी फुनगा में 77, पीएचसी बेनीबारी में 29, सीएचसी परासी में 26, पीएचसी बिजुरी में 16 तथा सीएचसी अमरकंटक में 3 किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है। सीएमएचओ डॉ. अलका तिवारी ने बताया कि टीकाकरण के बाद प्रत्येक बालिका को 30 मिनट तक चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है, ताकि किसी भी संभावित प्रतिक्रिया पर तुरंत ध्यान दिया जा सके। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा कि जिले की प्रत्येक पात्र किशोरी को इस अभियान से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि यह टीका भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करता है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए इस निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाएं।

मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के अनूपपुर जिला अध्यक्ष बने आरबी कोल

अनूपपुर। जल संसाधन विभाग में लेखपाल के पद पर कार्यरत आरबी कोल को एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ का अनूपपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संघ के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी द्वारा जारी संगठनात्मक आदेश के माध्यम से की गई। जारी आदेश के अनुसार आरबी कोल वर्तमान में जल संसाधन विभाग में सहायक वर्ग 2 (लेखपाल) के रूप में पदस्थ हैं। वे लंबे समय से कर्मचारी संगठनों और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके संगठनात्मक अनुभव, कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता और सक्रिय कार्यशैली को देखते हुए संघ ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। संघ द्वारा जारी आदेश में उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र ही अनूपपुर जिले में संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन करें और इसकी जानकारी प्रांतीय नेतृत्व को उपलब्ध कराएं। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि उनके नेतृत्व में जिले में संगठन को मजबूती मिलेगी और कर्मचारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। आरबी कोल इससे पहले भी विभिन्न कर्मचारी एवं सामाजिक संगठनों में महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान, अधिकारों की रक्षा और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें कर्मचारियों के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। उनकी नियुक्ति की जानकारी मिलते ही विभागीय कर्मचारियों और सहयोगियों में खुशी का माहौल देखा गया। कई कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वे संगठन को और अधिक मजबूत बनाते हुए कर्मचारियों की आवाज को शासन-प्रशासन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का कार्य करेंगे। संघ के पदाधिकारियों ने भी विश्वास व्यक्त किया है कि आर.बी. कोल अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता के बल पर संगठन को नई दिशा देंगे और कर्मचारियों के हितों के लिए सक्रिय रूप से कार्य।